

का ही दखल कब्जा है।

उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक 382 दिनांक 05.02.1985 द्वारा जिले के सभी अंचल अधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अनुमण्डल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अवैध जमाबंदी की सत्यता की जाँच किस प्रकार किया जाना है, उक्त पत्र की कड़िका 0.1 (एक में स्पष्ट रूप से निदेश है कि 31.03.57 तक अगर जमीन्दारी रसीद के आधार पर कर्मचारी द्वारा पहली रसीद काटी गयी है, तो वह सही है।

माननीय उच्च न्यायालय के सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0 75/99 (आर) में पारित आदेश से भी स्पष्ट है कि व्यक्ति विशेष के नाम लम्बी अवधि से कायम जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता। यह रूलींग जे0एस0सी0आर0 2001 पेज 206 में प्रतिवेदित है। इसी प्रकार का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय में डब्लू0पी0 (सी0) नं0 1327/2003 में दिया गया है जो जे0सी0आर0 2006 (3) पेज 430 में प्रतिवेदित है।

उक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी का दावा संगत कागजातों के आधार पर विपक्षियों के दावे से सबल है। निम्न न्यायालय के आदेश से सहमत होने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

फलतः निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, बरकट्टा श्री कामेश्वर प्रसाद के नाम चल रही जमाबंदी को पूर्ववत् बरकरार रखेंगे। इसकी एक प्रति अंचल अधिकारी, बरकट्टा को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता,  
हजारीबाग।

अपर समाहर्ता,  
हजारीबाग।

पत्रांक - 3162 दि. 17/12/85  
प्रतिनिधि भूमि अंचल अधिकारी, बरकट्टा  
को निम्न न्यायालय विनिष्ठा वाद - ए. 04/06-07 - कामेश्वर  
प्रसाद बनाम गनी पासवान का भूमि सुधार उप समाहर्ता के साथ  
सुचनापत्र एवं आवेदन कागजात प्रेषित।

21/12/85

अपर समाहर्ता  
हजारीबाग

आदेश की  
क्रम संख्या  
और तारीख

12.6.17

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अपीलाकर्ता के निवेदन में माइल च्यापलैन्स सर्वे  
741/1 हुआ दिनांक 14.7.17 को रखा है।

उ. प्रदा. विधि

17.7.17

अपीलाकर्ता - कांसात हाथर।  
विपक्षी - उपरिगत। दिनांक 18.8.17 को  
रखा है।

उ. प्रदा. विधि

18.8.17

अपीलाकर्ता - उपरिगत।  
विपक्षी - उपरिगत।

Heard the learned counsel of the  
respondent. The learned counsel of  
appellant is absent. Perused the  
record of the case and report of  
circumstances. Considering the  
fact that the appellant is in  
possession of land but does not  
have supporting document with respect  
to settlement or right of the land.  
The second party claims to have a settlement,  
but is not in possession of the land.  
Land is GM as per Khajyan. The C.O.  
is directed to remove all encroachments  
and decide as to the legality of settlement  
and take n.c. accordingly as per rules. 12/8/17

आदेश  
कार्रवाई के  
टिप्पणी तारीख